International Journal of Humanities and Social Science Invention
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 5 Issue 8 || August. 2016 || PP.70-72

आर्थिक विकास के साथ ही साथ नष्ट् होती हमारी संस्कृति एवं परंम्परा

डा. लता व्यास

व्याख्याता

चौधरी बल्लू राम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर

किसी देश का अर्थिक रूप से मजबूत होना, उस देश के निवासियों के लिए गर्व की बात होती है। हमारा देश भी लगातार सभी क्षेत्रों में अपनी सफलता के झण्डें गांड़ता चला जा रहा है। यहां की मेघा का ढंका आज सारे विश्व में बज रहा है, इतना सब होने के बाद भी हमारे जीवन मूल्यों में कमी दृष्टिगोचर होती है।

भारत की आत्मा तो उसके गांवों में बसती है, अगर भारत को जानना एवं समझना है तो पहले हमें उसके गांवों के बारे में जानना होगा। कांलातर में गांव की समाजिक संरचना एवं संगठन में अमूल-चूल परिवर्तन हुआ हैं। भारत सरकार द्धारा चालू की गई कुछ योजनाओं यथा- डीजिटल इंडिया. स्टाटअप इंडिया एवं सर्व शिक्षा अभियान. नरेगा तथा सूचना क्रान्ति ने इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हैं।

भारतीय ग्राम वासियों की जीवन शैली में अभूतपूर्व ढ़ंग से बदलाव आया है। भारतीय गांव आज आर्थिक रूप से सम्पन्न बन गए है। गाव की प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति बढ़ गई है। आज राज्य तथा केन्द्र दोनों ही सरकारे गांव की उन्नति के लिए काफी धन खर्च कर रहीं हैं। आज के गांव निश्चित रुप से पहले के जैसे नहीं रह गये है। आज हर एक गांव में सड़के, नहरें, पाठशालायें, टेलीविजन, मोटरसाईकिल, ट्रैक्टर आदि सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं । गावों में विकास की यह प्रकिया निरन्तर चल रहीं हैं। खेत जोतने के लिए अब किसान को बैलों पर निर्भर रहने की जरुरत नहीं रह गई हैं। जोताई से लेकर बोआई, मड़ाई आदि सभी चीजो की आधुनिक मशीने बाजार में उपलब्ध हैं।

आज गांव संक्रमण के ऐसे दौर से गुजर रहा हैं, जहां प्रत्येक ग्रामवासी आडम्बर युक्त जीवन जी रहा हैं। आज वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसे अन्य किसी ओर से कोई सरोकार नहीं हैं। किसी दूसरे की तरक्की को देखकर वे अपने मन में उसके प्रति ईष्या करते हैं। आज ग्रामीण समाज पहले जैसा स्थिर, कट्टर, पिछड़ा, रुढ़िवादी, असभ्य एवं संतोषी नहीं रहा हैं। ग्रामीण समाज में बदलाव की यह प्रकिया उसके विभिन्न आयामों पर चल रहीं हैं। चाहें वह सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक या फिर आर्थिक हो। ग्रामिणों ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी गतिशीलता दर्ज करवायी हैं। गांव अब सामाजिक ईकाई ही नहीं राजनीतिक ईकाई के रुप में उभर रहा हैं। आधुनिकीकरण तथा आर्थिक सुधारों के चलते जहां सकारात्मक परिवर्तन आये हैं वहीं साथ ही साथ नकारात्मक परिणाम भी सामने आये हैं, यथा- जातीय संघर्ष, गुटबाजी, छलकपट, नशाखोरी, आडम्बर, उपभोग की संस्कृृति का विकसित होना, अश्लीलता को बढ़ावा मिलना आदि। जिसके परिणामस्वरुप गांव का सरल एवं सादा जीवन जटिल एवं आडम्बरयुक्त बन रहा हैं। वहां उपभोक्तावाद लगातार अपने पैर पसार रहा हैं। जैसे-जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पूजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ जुडती जा रही हैं, वैसे-वैसे उसका भूमंडलीकरण होता जा रहा है और उस ग्रामीण समाज का शहरीकरण होता जा रहा हैं। पुराने मानक एवं मूल्य लगातार बदलते जा रहे हैं। वहां इसके स्थान पर नये प्रकार के तनाव एवं राग-द्वेष एवं द्वन्द्व पनप रहे हैं। रिश्तेदारी एवं नातेदारी संबंधी मूल्यों और प्रेम-व्यवहार में अंतर आ रहे हैं। अब वह धनार्जन के नये-नये तौर-तरीको से परिचित हो रहे हैं। अब उनके पास पूंजी का कोई विशेष अभाव नहीं रह गया हैं, जिसका प्रभाव गांवों में होने वाली मंहगी शादीयों या विवाहों या फिर भव्य कार्यक्रमों और राजनीतिक क्रियाकलापो में प्रत्यक्ष रुप से देखा जा सकता हैं।

इतना सब होने के बाद भी फिर भी ऐसा लगता है कि हमारे गाव पिछड़ते चले जा रहें है। जिसकी वजह से किसान खेती छोड़ते चले जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रो से उनका लगातार पलायन हो रहा हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि और इससे जुड़े हुये विभिन्न क्षेत्रों का सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम संक्षेप में जी0 डी0 पी0 कहते है, का योगदान 2009-2010 में महज 0.2

प्रतिशत ही था, जो यह दर्शाता है कि हमारी कृषि का भविष्य अन्धकारमय है। गांवों के नौजवान न तो कृषि में ही रूचि ले रहे है और न उन्हें गांव में रहना ही रूचिकर लगता है।

राष्टीय नमूना सर्वेक्षण के एक अध्ययन के मुताबिक लगभग 40 प्रतिशत किसान खेती छोड़ना पंसद करेगे यदि उन्हें ऐसा करने की छूट दे दी जाय। दुर्भाग्यवश, उनके लिए शहरी मलिन बस्तियों में जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। किसानों की सर्वाधिक बदतर स्थित आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र जैसे उन अग्रणी राज्यो में है जो 1991 में प्रारम्भ नयी आर्थिक नीतियों से खासे लाभान्वित हुए है, और प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से काफी आगे हैं। इन विकट स्थितियों के चलते इन राज्यों के हजारों किसानों ने आत्महत्या तक कर लिया। जिन किसानों ने आत्महत्या नहीं की है उनकी स्थिति आत्महत्या करने वाले किसानों से बहुत अच्छी नहीं हैं। आत्महत्या से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र का विर्दभ क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से देश के शेष गांवो के किसानों की स्थिति भी विर्दभ एवं उसके जैसे प्रभावित अन्य राज्यो के किसानो से अलग नहीं हैं।

आज विकास की इस दौड में गांवों की प्राचीन विरासत एवं परम्परा कहीं विलुप्त न हो जाये इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे गांव ही भारतीय संस्कृति एवं परम्पराओं के प्रतिबिम्ब है। इन गांवों से ही हमारी पुरातन परम्पराएं, रीति-रिवाज, प्रथाये, रूढ़ियां एवं संस्कृति आदि आज भी जीवित है। गांव की युवा पीढ़ी आधुनीक संचार साधनों का तो उपयोग करे मगर कहीं इसके चुंगल में न फंसकर रह जाये इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत हैं। संचार साधनों में हुई प्रगति का लाभ आज प्रत्येक ग्रामिण उठा रहा है। पहले जहां लोगों के पास टेलिफोन जैसी बुनियादी चीज नहीं थी, वहीं आज प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में आधुनिक मोबाइल सेट है। गांवों के प्रत्येक चट्टी-चैराहों पर साइबर कैफे खुले है और जहा नहीं खुले है वहां पर भी तेजी के साथ खुलते ही चले जा रहे हैं। इन साइबर ढाबों/साइबर कैफों पर गांवों के नौजवानों की भीड़ कभी भी देखी जा सकती है। गांवों में होने वाले इन परिवर्तनों के नकारात्मक प्रभाव भी अब सामने आ रहे है। इन प्रभावों ने गांवों की प्राचीन परम्परा और उसकी जड़ों को हिलाकर रख दिया है। गांव की प्राचीन परम्परा एक मुठ्ठी में बन्द रेत की तरह से फिसल कर बाहर निकलती चली जा रही है। इस स्थिति ने उसे किंकतर् व्यविमूढ़ बना दिया है। वह समझ नहीं पा रहा कि आने वाली नई तकनीकी का अपने गांव में स्वागत करे अथवा उसका विरोध करे। प्राचीन मान्यताओं तथा आधुनिकता के बीच में पड़ कर वह छटपटा रहा है, उसका दम फूल रहा है। एक दिशाहीनता का वह अनुभव कर रहा है। शीघ्रता से होते जा रहे शहरीकरण को वह बस मूक दर्शक बन करके देख रहा है। कृषि तथा पशुपालन जैसे व्यवसाय जो कि उसकी जीविका का एक आधार बिन्दु था अब उससे दूर होता चला जा रहा है। कृषि योग्य भूमि का व्यावसायिकरण होता चला जा रहा है। देश में इस समय लगभग छह लाख गांव है जिनमें से चार लाख गांवों में खाद्यान्न का उत्पादन होता हैं। जरुरत है उनको प्ररित करने की ताकि वे शिक्षा के साथ ही साथ आधुनिक कृषि ज्ञान को भी समझे तथा उसे सीखे। ''उत्तम खेती मध्यम बान '' यह पुरानी कहावत एकदम से सटीक है। सच तो यह है कि ग्रामीण विकास के बिना हमारे देश की उन्नति सम्भव ही नहीं है।

भारत के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी एक सत्य है कि इसके मूल्यों में कमी आयी है। फलस्वरूप शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में प्रतिवर्ष इजाफा देखने को मिल रहा है। ज्यों-ज्यों शिक्षा का व्यावसायिकरण होता गया वैसे ही इसके नैतिक मूल्यों में कमी देखने को मिल रही हैं। आज के विष्वविद्यालय केवल कागज की डिग्री बांटने वाले केन्द्र बन कर रह गये हैं। विष्व के टाप के दो सौ कालेजों की लिस्ट में हमारे देष के एक भी कालेज का नाम न मिलना हमे अब कोई अचम्भीत नहीं करता। अपने देष से काफी छोटे-छोटे कई अन्य देषों के कालेजो के नाम इस लिस्ट में षामिल है।

अभी हाल में दुनियां के जाने-माने विष्वविद्यालयों के एक संगठन के आकलन से एक रिर्पोट आई है। यूनिवर्सिटास-21 की इस रिर्पोट ने उच्च षिक्षा के क्षेत्र में हमारी पोल ही खोल दी है। इस रिर्पोट के अनुसार, उच्च षिक्षा में भारत का स्थान 48 वां है। इस सूची में हमारे देष का स्थान ब्रिक देषों, ब्राजील, रूस एवं चीन के बाद सबसे अंत में आता है। इस सूची में पहला स्थान अमेरिका को दिया गया है, वहीं दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे पर कनाडा का नाम है। हमारे देष के विष्वविद्यालयों की इस दयनीय दषा के लिए केन्द्र और राज्य सरकारे दोनों ही बराबर की जिम्मेदार हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिर्पोट बतलाती है कि देष में अभी भी 13 लाख से भी ज्यादा षिक्षकों की कमी है। कोई भी देष अपनी प्रगति एवं उपलब्धियों पर तब तक गर्व नहीं कर सकता जब तक कि उसके यहां षिक्षा का स्तर उच्च न हो। सम्पूर्ण भारतवर्ष के विकास के लिए समाज के प्रत्येक

वर्ग को सस्ती और तकनीकी, ज्ञानवर्द्धक शिक्षा सुलभ कराई जानी चाहिये। वर्तमान में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वह छात्रों को भम्रित करने का ही काम अधिक कर रही है। शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे कि छात्र अपने जीवन काल में कुछ कमा खा सके। राष्ट्र की बेरोजगारी कम हो सके तथा सभी को आजिविका चलाने का अधिक से अधिक अवसर मिल सके। शिक्षा उत्पादोन्मुख होनी चाहिए, क्याकि उत्पादन में वृद्धि ही आर्थिक विाि‍स का मूल आधार है। गांधीजी ने शिक्षा के क्षेत्र में इस कमी को पहचान लिया था। उन्होंने शिक्षा को उत्पादकत्ता से जोड़ने का प्रयास किया था। आज का समय आधुनिक है। हम आधुनिक समाज में जी रहे है, अतः शिक्षा को भी तकनीकि होना चाहिए, जिससे कि उद्योग का विकास हो सके और भारत उद्योगों के विकास से और आगे बढ़ सके। आर्थिक विकास के क्षेत्र में हुए विभिन्न शोध इस बात की पुष्टि करते है कि शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी आर्थिक विकास में अपना लगभग 50 फीसदी से ज्यादा ही योगदान देते है। अतः हमें शिक्षा के साथ ही साथ विज्ञान के भी महत्व को समझना होगा। हमारे देश के वैज्ञानिकों का डंका आज पूरे विश्वभर में बज रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे ही युवा वैज्ञानिक आज अच्छे वेतन के लालच में अन्य विकसीत देशों की तरफ आर्कषित हो रहे है।

सन्दर्भ ग्रन्थः

1. इण्टरनेशनल सेमिनार, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ- डाॅ0 नवीन शंकर पाण्डेय
2. जनरल ज्ञान दायिनी समाज विज्ञान शोध पत्रिका,(पृष्ठ 147) दिसम्बर 2012
3. भारतीय अर्थव्यवस्था, डाॅ0 जे0 सी0 पन्त एवं डाॅ0 एस0 सी0 जैन
4. प्रतियोगिता किरण (हिन्दी मासिक) अगस्त, 2003
5. आई0 ए0 एस0 किरण (हिन्दी मासिक) अगस्त, 2003